थानेदार चुलबुल पांडे फिर हुआ सक्रिय एन आई टी में

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपने आप को चुलबुल पांडे समझने वाला ए एस आई सुरेन्द्र स्वामी कुछ माह तक अज्ञातवास में रहने के बाद अब फ़िर एन आई टी क्षेत्र के थाना एस जी एम नगर की चौकी नम्बर 3 में तैनाती पा गया है। इससे पहले थाना एन आई टी में तैनाती के दौरान इसने जो गंद मचाया था उसके चलते जाना तो इसको जेल में चाहिये था, परन्तु कुछ बड़े अफ़सरों की सरपरस्ती के चलते तबादलों से ही इसका काम चल गया। लेकिन अब 3 नम्बर में आने पर इसने अपना जलवा फ़िर से दिखाना शुरू कर दिया है।

दिनांक 23 फ़रवरी को रात करीब साढे आठ बजे अनिल निवासी 3 ए/147 ने 100 नम्बर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया कि उनके सामने पार्क में 8-10 लड़के हथियारों से लैस होकर आये और आते ही लव कटारिया नामक एक लड़के पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। करीब एक घंटे तक पी सी आर का इन्तज़ार करने के बाद स्थानीय चौकी को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर 5 हमलावर लड़कों व एक बाइक को कब्ज़े में ले लिया। उधर गंभीर घायल अवस्था में लव कटारिया को एस्कॉर्ट-फ़ोर्टिस अस्पताल में उसके परिजनों ने भर्ती करा दिया। गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों ने उसे बयान देने के अनफ़िट करार दे दिया।

पुलिस को सूचित करने वाले अनिल

एनआईटी का चुलबुल पाण्डे

ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि हमलावरों के हाथ में बेसबाल के बल्ले डंडे व एक के पास पिस्टल थी जिससे चलने वाली गोली की आवाज़ सुन कर ही वह मौके पर पहुंचा था और किसी अनहोनी को रोकने के इरादे से 100 नम्बर पर फ़ोन किया था। अनिल ने यह बताया कि जब वह मौके पर पहुंचा तो हमलावर उसे भी मारने को दौड़े थे। वह भाग कर अपने घर में घुसा तो हमलावर भी पीछे-पीछे उसके घर में घुस आये और उसे भी बुरी तरह से पीटा क्योंकि उसने पुलिस को फ़ोन किया था। पीटने के अलावा हमलावरों ने लव कटारिया की जेब में मौजूद नकद 20-22 हज़ार रुपये भी लूट लिये।

अनिल के उक्त बयान पर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148,149,323, 506, तथा 25-54-59 शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा नम्बर 78 दिनांक 24.2.15 को दर्ज कर लिया। तफ़्तीश चुलबुल पांडे के हिस्से में आ गयी। अपनी आदत के मुताबिक उसने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने पकड़े गये 5 में से 2 लड़कों व उनकी बाइक को छोड़ दिया। लव कटारिया की जेब से जो नकदी लूटी गयी उसको एफ़ आई आर में लिखा ही नहीं गया। पिस्टल बरामद करने का प्रयास करने की बजाय पिस्टल के इस्तेमाल की बात को ही थानेदार साहब झुठला रहे हैं।

पुलिस की ढुलमुल कार्यवाही का यह हाल तो तब है जब हमले की लगभग सारी वारदात सी सी टी वी कैमरों में कैद हैं। पुलिस द्वारा लगाई गयी धारायें एक तो पहले से ही कमज़ोर हैं, दूसरे पुलिस की ढीली-मीली तफ़्तीश हमलावरों के हौंसले और बढायेगी। जनता के भारी दबाव के चलते पुलिस ने 3 और हमलावरों को गिरफ़्तार कर लिया है। इससे गिरफ़्तारों की कुल संख्या अब 6 हो गयी है। लेकिन खबर लिखे जाने तक कटारिया का बयान पुलिस ने दर्ज नहीं किया।

पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के चलते ही असामाजिक तत्वों के हौंसले बढते हैं; वे क़ानून को अपने ठेंगे पर रखते हैं और वे बेख़ौफ़ होकर गुंडागर्दी करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गायब होता भूजल

पानी का महत्त्व बताते हुए रहीम ने लिखा था-

रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून

पानी गये न ऊबरै, मोती, मानुष, चून।

भूजल के बेतहाशा दोहन ने आज हमें वहां पहुंचा दिया है कि जिंदगी के लिये जरूरी न्यूनतम पानी भी अब धरती के गर्भ में नहीं बचा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भूजल में भारी गिरावट पर हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आयी है वह काफ़ी बेचैन करनेवाली है। राजधानी और उसके आस-पास के क्षेत्र- गुड़गांव, फ़रीदाबाद और गाजियाबाद में बिल्डिंग और उद्योगों में अत्यधिक भूजल के दोहन से स्थिति बेकाबू हो गयी है। गुड़गांव सहित हरियाणा के लगभग सभी ज़िलों में भविष्य के लिये उपलब्ध भूजल की मात्रा नकारात्मक है। दिल्ली में जलबोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति और नये बोरवेल पर रोक लगाये जाने के चलते भूजल पर निर्भरता में थोड़ी कमी आयी है, हालांकि अवैध रूप से भूजल का दोहन आज भी जारी है।

'भारत के परिवर्तनीय भूजल संसाधन' शीर्षक एक अध्ययन में बताया गया है कि दिल्ली के 27 खंडों में हर साल 31 करोड़ धन मीटर भूजल से आपूरित हो जाता है जबकि वहां पानी की अनुमानित सालाना खपत सिंचाई के लिए 14 करोड़ घनमीटर, उद्योग और घरेलू खर्चों के लिये 25 करोड़ घनमीटर है। यहां प्राकृतिक रूप से पूर्ति और खपत का अनुपात 137 प्रतिशत है। यह तथ्य पानी के अन्धाधुन्ध दोहन की भयावह तस्वीर पेश करता है। गुड़गांव में सालाना भूजल का दोहन 54, 418 हेक्टेयर मीटर है जबकि बरसात से मात्र 26,720 हेक्टेयर मीटर जल की पुन:पूर्ति हो पाती है। इस तरह यहां भविष्य के लिए उपलब्ध जल की मात्रा नकारात्मक है। यहां भूजल की पूर्ति और खपत का अनुपात 226 प्रतिशत है जो दोहन की चरम स्थिति को दर्शाता है। फ़रीदाबाद इस मामले में थोड़ा ठीक है जबकि पूरे हरियाणा राज्य की स्थिति नकारात्मक है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर भी अत्यधिक दोहन क्षेत्र में शामिल हैं।

दिल्ली के आस-पास के बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन ट्रिब्यूनल की मनाही के बावजूद भवन निर्माण कम्पनियां भूजल का अत्यधिक दोहन कर रही हैं। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि जल संरक्षण करके भूजल की क्षतिपूर्ति कैसे की जाय। ये इस बात से भी बेफ़िक्र हैं कि धरती के गर्म में उपलब्ध भूजल सीमित है। यह बैंक में जमा धन की तरह है। यदि इसका खर्च और आमदनी का अनुपात बिगड़ जाय तो आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। वैसा ही संकट आज भूजल को लेकर है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने एक शपथ पत्र पेश किया था जिसके मुताबिक यहां भवन निर्माण करनेवाले बारिश से इकट्ठा हुए जल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जितनी मात्रा में वहां जल का इस्तेमाल हुआ है, उतनी तो बारिश भी नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार ओर बिल्डरों से जवाब मांगा है। जाहिर है कि इस तरह के कागजी घोड़े दौड़ाकर इन क्षेत्रों में आनेवाली गम्भीर समस्या से नहीं बचा जा सकता। इस सवाल को हल करने के लिये एक जन आंदोलन की जरूरत है जो सबको रोजमर्रा की जरूरत के लिये उचित मात्रा में पानी मुहैया कराना सुनिश्चित करे और जल संरक्षण के प्रति समग्र दृष्टिकोण और सही योजना को कड़ाई से लागू करवाये।

-देश विदेश

भविष्य निधि से श्रमिकों को वंचित करने की ओर

फ़रीदाबाद (म.मो.) जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तभी से उद्योगों को बढ़ावा देने के नाम पर श्रमिकों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है और मजदूरों के नाम पर दुकान चलने वाली तथाकथित ट्रेड यूनियनें चुप हैं। श्रम मंत्रालय ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने के नाम पर कंपनियों की जांच पूरी तरह से बंद करवा दी है जिसके परिणाम स्वरूप आज खुलेआम मजदूरों को भविष्य निधि के लाभों से वंचित किया जा रहा है। जहाँ पहले कम्पनी वालों में भविष्य निधि विभाग का थोडा बहुत डर तो रहता था लेकिन अब उन्हें इस विभाग की जरा भी परवाह नहीं है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब कोई भी इन्स्पेक्टर किसी भी कम्पनी में हो रही भविष्य निधि की चोरी को चेक नहीं कर सकते है इसके लिए केन्द्रीय स्तर पर एक अलग से सी ए आई यू यूनिट बनाई है जो भी इन्स्पेक्सन करनी होगी उसके लिए अब केन्द्रीय स्तर से ही प्रोग्राम आएगा क्षेत्रीय आयुक्त को भी अब किसी भी कम्पनी को चेक करवाने का अधिकार नहीं है इसके लिए पहले पहले सूचना सी ए आई यू में भेजनी होगी वहां से भी जरुरी नहीं है कि सभी भेजी गई लिस्ट की ही जांच करवाई जाये ये उनकी मर्जी है कि वो किस कम्पनी की जांच करवाना चाहते हैं इन्स्पेक्सन के लिए अब श्रम मंत्रालय ने एक पोर्टल बनया है जिसका नाम उन्होंने श्रम सुविधा पोर्टल रखा है इस पोर्टल पर भविष्य निधि, इ एस आई सी, कोल माइंस, व सी एल सी इस प्रकार चार विभागों का एक संयुक्त पोर्टल बनया है सुनने व देखने में तो ये ठीक लगता है परन्तु इसके बहाने से श्रमिकों के हित पूरी तरह से कुचले जा रहे हैं। अब जो भी इन्स्पक्सन होगी उसकी लिस्ट श्रम मंत्रालय श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से सम्बंधित कार्यालय को भेजेगा उस लिस्ट के अनुसार केवल छियानवे घंटे में एक इन्स्पेक्टर को इन्स्पेक्सन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करनी ही पड़ेगी अन्यथा इन्स्पेक्टर की वार्षिक रिपोर्ट में नकारात्मक प्रविष्टि दर्ज हो जाएगी। कहने को तो ये छियान्वें घंटे हैं जो अभी कुछ दिन पहले तक ये बहत्तर घंटे यानि तीन दिन जिसमें रात दिन शामिल हैं, थे जो वास्तव में आठ घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चौबीस घंटे ही थे जो अब बत्तीस घंटे कर दिए गए हैं। अब कोई इनसे पूछे कि क्या इन्स्पेक्टर रात दिन लगातार इन्स्पेक्सन ही करेगा उसे अपने नित्यक्रिया के वा दूसरे कार्य भी करने होते हैं उसे रात को सोना भी है। इन्ही तथाकथित छियान्वें घंटों में एक इन्स्पेक्टर को विभाग द्वारा आवंटित अन्य कार्य भी करने होते हैं। जबकि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्देशों के अनुसार एक इन्स्पेक्टर को कार्य दिवस यानि प्रात: नौ बजे से सांय साड़े पांच बजे तक ही इन्स्पेक्सन करना होगा। अब कोई इनसे पूछे कि ये छियान्वें घंटे कैसे होते हैं द्यइस जल्दबाजी में किसी भी कम्पनी का इन्स्पेक्सन भलीभांति हो ही नहीं सकता है और सरकार चाहती भी यही है कि जो भी कम्पनी जो रिकार्ड दिखाना चाहती है वही देखा जाये। हालांकि इसके लिया भविष्य निधि विभाग भी कम उत्तरदाई नहीं है भविष्य निधि विभाग के इन्स्पेक्टर वा इसके सम्बंधित अधिकारी भी पहले उन्ही कंपनियों का हर साल इन्स्पेक्सन करते थे जो ठीक ठाक काम करती रहती थी और फीस भी ठीक ठाक दे देती थी इस कारण हजारों कम्पनियाँ ऐसी हैं जिनका आज तक एक भी इन्स्पेक्सन नहीं किया गया सैंकड़ों कम्पनियाँ और ठेकेदार तो इस बीच मजदूरों का पैसा खा पीकर भाग गए या दूसरे नाम से अपना कारोबार फिर शुरू कर दिया। लेकिन आज कल जो सिस्टम इन्स्पेक्सन का बनाया है वह तो बिलकुल ही कंपनियों के हितों देखते हुए बनाया गया है। यहाँ यह भी गौर तलब है कि अधिकांश कंपनियों ने कंसल्टेंट रखे हुए हैं जिनके पास पचासों से लेकर सैंकड़ों कंपनियों का कार्य होता है ये कंसल्टेंट समय पर पर जान-बूझकर रिकार्ड इन्स्पेक्टर को दिखाते ही नहीं हैं ताकि इन्स्पेक्टर थक हार कर कोई रिकार्ड देख ही नहीं पाए और चोरी पकड़ में ही नहीं आये अब चूँकि इन्स्पक्टर को बत्तीस घंटे में अपनी रिपोर्ट उपलोड करनी होती है इस कारण वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है।

इसके अतिरिक्त श्रम मंत्रालय ने भविष्य निधि का कोड नंबर लेना आसान बना दिया है कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी फर्म या कम्पनी का पंजीकरण कर सकता है चाहे उसके पास एक भी मजदूर न हो कहने व देखने में तो ये अच्छा लगता है लेकिन ऐसे पंजीकरणों से विभाग का काम बहुत बढ़ गया है इसमें भी एक इंस्पेक्टर को अपना, कम्पनी मालिक या ठेकेदार का फोटो लाना भी आवश्यक कर दिया है जबकि किसी भी इंस्पेक्टर को न तो कोई आधुनिक तकनीक के मोबाइल और न ही कम्पूटर लैपटॉप आदि ही उपलब्ध कराएँ हैं। इन कोड नंबर लेने वालों के अनेक पते तो फर्जी पाए जा रहे हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जब कोड नंबर लेने में ही फर्जी पता व व फर्जी दस्तावेज लगाये जा रहे हैं तो बाद में ये मजदूरों के साथ क्या नहीं करेंगे।

भविष्य निधि विभाग के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि विभाग में स्टाफ की भारी कमी है जिसके कारण इंस्पेक्टर कार्य के बोझ से दबे हुए हैं सरकार के इस रुख के कारण उन्हें अत्यधिक तनाव मे कार्य करना पड रहा है। इसी तनाव को देखते हुए आज कल कोई भी लेखा अधिकारी इंस्पेक्टर बनना ही नहीं चाहता है।

खुद मियां फजहीत दूसरों को नसीहत

पलवल (म.मो.) यदि किसी को भारतीय राजनीति का असली चेहरा देखना हो तो वो पलवल के विधायक करण सिंह दलाल को देख सकता है। सन दो हज़ार से दो हज़ार पांच तक बतौर प्रसाशनिक सुधार आयोग के चेयरमैन के पद पर एक कबिनेट मंत्री स्तर की सुविधा प्राप्त व भूपिंदर हुड्डा के समधी होने के नाते दूसरा मुख्यमंत्री माने जाने वाले करण सिंह दलाल को आज पलवल क्षेत्र की समस्याएं याद आने लगी हैं । इसी विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने अनेक जनहित के उन मुद्दों को उठाया जो पिछले दस वर्ष से इन्हीं की सरकार रहते पूरे नहीं हुए समाचारपत्रों में इन पर विधायक द्वारा पूछे गए सवालों पर पलवलवासी आपस में चर्चा कर रहें हैं कि ये समस्याएं इनको दस वर्ष तक दिखाई नहीं दी थी अब एक दम से इन्हें के एम पी जैसे अति जरुरी प्रोजेक्ट याद आने लगें हैं। चुनावों में करण सिंह दलाल ने वे सभी हथकंडे अपनाये जो आज भारतीय राजनीति में अपनाये जा रहें हैं। अथाह पैसा जातिवाद के कारण चुनाव जीतने वालों के मुख से भ्रष्टाचार के विरोध की बातों पर एक जागरूक नागरिक खूब हँसता है। विधान सभा चुनावों से पहले करण सिंह दलाल ने बड़े बड़े बोर्ड लगवा कर पिछले दस वर्ष में पलवल को मिली सरकारी ग्रांट का खूब प्रचार किया था जब पलवल को कई सौ करोड़ की ग्रांट आई थी तो वह गई कहाँ उससे तो आज पलवल रोहतक की तरह पेरिस बन जाना चाहिए था।

नीलम चौक से रेलवे रोड़ पर स्थित प्लाट नं. 5सी-4 बीपी के सामने सडक तक की सरकारी जमीन घेर कर कबाड़े का गोदाम बना रखा है जगजीत सिंह डिया ने। दुखी पड़ोसियों की शिकायत जब किसी ने भी नहीं सुनी तो मजदूर मोर्चा ने 1-15 जनवरी के अंक में पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके उपरान्त कुछ दिन तो यह जगह साफ रही, परन्तु अब फिर से कबाडे का ढेर यहां लगा दिया गया है, इससे पड़ोसी व आने-जाने वाले लोग बेहद परेशान रहते हैं।